

ममता बनर्जी और बंगाल गवर्नर के बीच अब आ गया नया विवाद

● ताबड़तोड़ 8 बिल खारिज करने पर एससी पहुंची



टीएमसी सरकार

नई दिल्ली (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर ममता बनर्जी और गवर्नर सीवी आनंद बोस के बीच टन गई है। ममता सरकार के आठ विधेयकों को

गवर्नर बोस द्वारा खारिज करने से यह नया विवाद उपजा है। ममता सरकार ने गवर्नर के फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बंगाल सरकार की वकील आस्था शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ से तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया है। याचिका में कहा गया है कि गवर्नर ने बिना कोई कारण बताए आठ विधेयकों को खारिज कर दिया है।

आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम की अब बढ़ सकती है मुश्किल

● जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ हत्या के प्रयास



का मुकदमा दर्ज

हैदराबाद (एजेंसी)। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी मुश्किल में फंसे नजर आ रहे हैं। जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ हत्या के प्रयास का

मामला दर्ज किया गया है। उनके अलावा चार अन्य के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है, जिसमें दो आईपीएस अधिकारी और दो रिटायर अधिकारी भी शामिल हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि यह केस टीडीपी विधायक रघुराम कृष्ण राजू की शिकायत पर दर्ज किया गया है। रेड्डी के अलावा आईपीएस अधिकारी पीवी सुनील कुमार, सीतारामजानेयुल और रिटायर्ड पुलिस अधिकारी आर विजय पॉल के नाम भी शामिल हैं।

हुंडा के करीबी, जेजेपी और बीजेपी को भी चटाई थी धूल

● सोनीपत के मेयर निखिल मदान ने छोड़ी



कांग्रेस, बीजेपी में शामिल

सोनीपत (एजेंसी)। नगर निगम सोनीपत के मेयर निखिल मदान को दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में कांग्रेस छोड़कर अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। इस अवसर पर प्रदेश के

मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मनोहर लाल ने कहा कि बीजेपी सरकार की कार्यशैली से प्रभावित होकर मेयर निखिल मदान ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। वे मेयर निखिल मदान का बीजेपी परिवार में स्वागत करते हैं। वहीं, मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी ने कहा कि निखिल मदान विकास को लेकर हमेशा तत्पर रहते हैं।

अंतरिम जमानत के बाद सीएम केजरीवाल को फिर लगा झटका

● दिल्ली की अदालत ने 25 जुलाई तक बढ़ाई



न्यायिक हिरासत

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को ईडी वाले मामले में तो अंतरिम जमानत मिल गई, लेकिन सीबीआई वाले केस में उन्हें झटका लगा है।

दिल्ली की राजउ एवेन्यू कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी है। बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी और सीबीआई दोनों ने उन्हें अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार किया था। केजरीवाल ने दोनों ही गिरफ्तारी को चुनौती दी है। सीबीआई वाली गिरफ्तारी पर दिल्ली हाई कोर्ट 17 जुलाई को सुनवाई करेगा। सीएम केजरीवाल को सुबह 11 बजे के लगभग सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली।

संक्षिप्त समाचार

मुझसे मिलने वाले स्थानीय आधार कार्ड लेकर आएंगे

● कंगना बोली-मिलने का कारण भी लिखकर लाएं, कांग्रेस बोली- हमारे दरवाजे सबके लिए खुले



मंडी (एजेंसी)। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौट ने कहा है कि उनसे मिलने

वाले मंडी क्षेत्र का आधार कार्ड लेकर आएंगे। मिलने आने वाले लोगों को अपने आने का मकसद कागज पर लिखकर लाना होगा। कंगना ने गुरुवार को मंडी के पंचायत भवन में आयोजित जनता से संवाद कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यहां पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा- हमारे प्रदेश में पूरे देश से बहुत सारे पर्यटक आते हैं, इसलिए मिलने आने वाले लोगों के पास मंडी क्षेत्र का आधार कार्ड होना जरूरी है। लोगों की समस्या या मिलने का कारण भी कागज पर लिखकर ही लाएं।

राज्य नहीं कर सकते

हाईवे बंद, इसे जल्द

खोला जाए

● शंभू बॉर्डर को लेकर हरियाणा सरकार से बोला सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (एजेंसी)। शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार की याचिका पर कहा कि कोई राज्य हाईवे को कैसे रोक सकता है। किसान भी देश के नागरिक हैं। उनकी



समस्याओं का समाधान करना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार को काम यातायात को नियंत्रित करना है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट के उस फैसले के बाद आई है जिसमें उसने सहाहभर में शंभू बॉर्डर को खोलने का आदेश दिया था। शंभू बॉर्डर पर किसान पिछले 5 महीने से धरने पर बैठे हैं।

हार-जीत लगी रहती है

न करें अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल

● स्मृति ईरानी के खिलाफ भर्द के कमेंट करने वालों से राहुल गांधी ने की अपील

अमेठी (एजेंसी)। स्मृति ईरानी पर भर्द के कमेंट करने वालों को लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने नसीहत दी है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोगों से ऐसा न करने के लिए कहा। राहुल ने लिखा कि हार-जीत जीवन में लगी रहती है। मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि स्मृति ईरानी जी या किसी अन्य



नेता के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई अपमानजनक या भर्द टिप्पणी न की जाए। किसी का अपमान करना या किसी को नीचा दिखाना यह शक्तिशाली होने का नहीं कमजोर होने का प्रदर्शन करना है। किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए।

ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, 20 मीटर घसीटता ले गया

ग्वालियर में बहन-भाई और डेढ़ साल के भांजे की मौत; दो घंटे तक चक्काजाम



मालती कुशवाहा मृतक करुण कुशवाहा मृतक मोहित कुशवाहा मृतक

ग्वालियर (नप्र)। ग्वालियर में ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे के बाद ट्रक बाइक को 20 मीटर तक घसीटता ले गया। घटना भाई-बहन और डेढ़ साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि तीन साल की बच्ची घायल हो गई। मौके पर मौजूद गुस्साए लोगों ने दो घंटे तक चक्काजाम किया। घटना शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे

ग्वालियर-झांसी हाइवे पर सिकरौदा सिरोलकी की है। मृतक करुण कुशवाहा, उसकी बहन मालती कुशवाहा (24) पत्नी रवि कुशवाहा, मोहित (डेढ़ साल) पिता रवि कुशवाहा हैं। वहीं, तीन साल की बेटी एकता घायल हो गई। ग्वालियर में पुरानी छवनी रायक गांव के रहने वाले करुण कुशवाहा के चचेरे भाई की गुरुवार को शादी थी। शादी में

भितरवार से उसकी बहन मालती अपने दोनों बच्चों मोहित व एकता (3) के साथ आई थी। शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे करुण बहन और भांजे-भांजी को ससुराल छोड़ने बाइक से निकला था। वह सिरोल थाना क्षेत्र के सिकरौदा तिराहा पर पहुंचा। यहां सामने से तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी।

20 मीटर तक बाइक को घसीटता ले गया ट्रक- टक्कर के बाद ट्रक बाइक के नीचे फंस गई। ट्रक बाइक सवारों को रौंदता हुआ करीब 20 मीटर तक घसीटता ले गया। ट्रक ड्राइवर मौके से भाग गया। बच्ची उचट कर दूर जा गिरी। घायल बच्ची को हॉस्पिटल पहुंचाया। इधर, परिजन ने भी मौके पर पहुंचकर हंगामा कर दिया। परिजन ने शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। झांसी व ग्वालियर की ओर जाने वाले वाहनों की कतार लग गई। सिरोल थाना प्रभारी आलोक भदौरिया से आक्रोशित परिजन की झुमाझटकी भी की।

केंद्र का ऐलान, 25 जून 'संविधान हत्या दिवस' घोषित

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' घोषित कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार 12 जुलाई को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। सरकार ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया है। शाह ने लिखा, 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट दिया था। लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया गया और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाना इस बात की याद दिलाएगा कि उस दिन क्या हुआ था और भारत के संविधान को कैसे कुचला

नोटिफिकेशन जारी, 1975 में इसी दिन लगी थी इमरजेंसी



गया था। ये भारत के इतिहास में कांग्रेस द्वारा लाया गया एक काला दौर था। उधर, कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले को एक और सुर्खियां बटोरने वाली कवायद

बताया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, यह नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री की एक और सुर्खियां बटोरने वाली कवायद है, जिसने दस साल तक अघोषित आपातकाल लगाया था। उसके बाद भारत के लोगों ने उसे 4 जून, 2024 को एक निर्णायक व्यक्तिगत, राजनीतिक और नैतिक हार दी- जिसे इतिहास में मोदी मुक्ति दिवस के रूप में जाना जाएगा। इस साल 25 जून को इमरजेंसी की 49वीं बरसी थी। इससे एक दिन पहले यानी 24 जून को 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में विपक्षी सांसदों ने संविधान की कॉपी लेकर शपथ ली थी।

वायुसेना को 15 अगस्त तक मिलेगा पहला तेजस मार्क 1ए

● अमेरिकी कंपनी सितंबर-अक्टूबर से जीई-404 इंजन की सप्लाई करेगी, इसमें एडवांस्ड स्कार और सेल्फ डिफेंस की क्षमता



मार्क-1ए फाइटर जेट (तेजस) 15 अगस्त तक डिलीवर कर देगी। सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन में दिक्कतों और जीई-404 इंजन की सप्लाई में देरी के

कारण इसमें रुकावट आ रही थी। अब अमेरिकी इंजन निर्माता कंपनी जीई की तरफ से कन्फर्मेशन दे दिया है, जिसके बाद इंजन की सप्लाई सितंबर-अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। इससे पहले फरवरी-मार्च में डिलीवरी होनी थी। एचएएल इंजन की डिलीवरी

आतंकी साजिश मामले में एनआईए का बड़ा ऐक्शन

2 दहशतगर्दों के खिलाफ दाखिल हुई चार्जशीट, कई खुलासे

नई दिल्ली (एजेंसी)। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने आईएस आतंकी साजिश मामले में 2 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर किया है। ये दोनों ग्लोबल टेरर नेटवर्क के औरंगाबाद स्थित छत्रपति संभाजीनगर से जुड़े मॉड्यूल में शामिल थे। एनआईए ने इस साल फरवरी में कई जगहों पर तलाशी के बाद



एजेंडे को बढ़ावा देने की साजिश का आरोप है। दोनों ने पूरे भारत में संवेदनशील स्थानों पर आतंकी हमलों के लिए युवाओं को भर्ती करने की साजिश रची थी। मुंबई स्थित एनआईए स्पेशल कोर्ट में शुक्रवार को यह आरोप पत्र दायर किया गया।

हाथरस हादसे पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार

कहा-हाईकोर्ट जाएं, याचिका में जांच कमेटी की मांग की गई थी

लखनऊ (एजेंसी)।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हाथरस भगदड़ मामले पर दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि घटना परेशान करने वाली है, लेकिन ऐसे मामलों में हाईकोर्ट ही पर्याप्त है। कोर्ट ने याचिका लगाने वाले को हाईकोर्ट जाने को कहा। इस जनहित याचिका में हादसे की जांच की मांग की गई थी। 2 जुलाई को दाखिल याचिका में कहा गया था- जांच के लिए पांच एक्सपर्ट की टीम गठित की जाए। सुप्रीम कोर्ट के



रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच हो। याचिका सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला एवं जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच में सुनवाई के लिए आई। अधिवक्ता विशाल तिवारी ने दायर याचिका में घटना पर उत्तर प्रदेश सरकार को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने एवं लापरवाह

भाजपा सरकार में निवेश डेस्टीनेशन बना मप्र : उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल

भोपाल (नप्र)। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा में कहा कि प्रदेश में इस बार सभी 29 की 29 सीटें जीतकर रिकॉर्ड बनाया गया है। पार्टी हर चुनाव में प्रयास करेगी कि यह रिकॉर्ड हमेशा बना रहे। विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हमें भरोसा था कि केंद्र और राज्य की जनहितैषी योजनाओं के कारण हमें चुनाव में प्रचंड जीत मिलेगी और हुआ भी ऐसा ही। मध्यप्रदेश अब भाजपा का गढ़ बन चुका है। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि 3 जुलाई को प्रदेश सरकार ने 3 लाख 65 हजार करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया। यह पिछले बजट की तुलना में 16 प्रतिशत की वृद्धि थी। आने वाले पांच सालों में बजट का आकार 7 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। जब इस तरह का बजट आता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है। पहले विकास कार्यों के लिए धन की कमी रहती थी और यह हमारे प्रदेश में एक बड़ी चुनौती थी। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि 4 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड



धारक हमारे प्रदेश में हैं। अब तो 70 साल से अधिक उम्र के लोगों को भी इस योजना का लाभ मिल रहा है। हमने संविदा कमी, आशा कार्यक्रम, सहायिकाओं को भी इस योजना में शामिल किया है। हमारी सरकार कालिटी एजुकेशन पर फोकस कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी की सरकार ने पीएम कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस पर काम किया और 14 जुलाई को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी इंदौर से इसका शुभारंभ करेंगे। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने

के लिए सरकार आने वाले समय में करीब 40 हजार स्वास्थ्यकर्मियों की भर्ती करेगी। श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे हेल्थ सेक्टर या फिर एजुकेशन का सेक्टर, मध्य प्रदेश को अब निवेश के डेस्टिनेशन के तौर पर देखा जाने लगा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मोदी जी की चार जातियों गरीब, युवा, महिला व किसानों के लिए कार्य कर रही है। इस अवसर प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष उषा अग्रवाल, प्रदेश प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी एवं मिलन भागवत उपस्थित रहे।

अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की मतगणना की सभी तैयारियां पूरी

13 जुलाई को सुबह 8 बजे से होगी मतगणना

भोपाल (नप्र)। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजेश कौल ने बताया कि विधानसभा उप निर्वाचन 2024 के अंतर्गत छिंदवाड़ा जिले की विधानसभा क्षेत्र क्र.-123 अमरवाड़ा (अ.ज.जा.) की मतगणना शनिवार, 13 जुलाई को सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगी। यह मतगणना शासकीय पीजी कॉलेज भवन, छिंदवाड़ा में दो हॉल में कराई जाएगी। मतगणना के सभी इंतजाम किए जा चुके हैं। रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को सुरक्षा मापदंडों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गये हैं।

332 मतदान केन्द्रों की मतगणना के लिये लगाई जाएगी 17 टेबल्स: अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के 332 मतदान केन्द्रों में मतदाताओं द्वारा ईवीएम में डाले गये मतों की गणना के लिए 17 टेबल्स एवं पोस्टल बैलेट्स की मतगणना के लिये 4 टेबलें लगाई जाएगी। मतगणना लगभग 20 राउंड्स में सम्पन्न कराई जाएगी।

मतगणना स्थल पर रहेगी त्रि-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था: मतगणना स्थल पर त्रि-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। केवल अधिकृत पासधारी व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे। कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति मतगणना

सेंटर पर प्रवेश नहीं करेगा। मतगणना कर्मियों का त्रि-स्तरीय रेण्डमाइजेशन होगा। प्रथम एवं द्वितीय स्तर का रेण्डमाइजेशन हो चुका है। तृतीय रेण्डमाइजेशन 13 जुलाई को सुबह 5 बजे किया जायेगा।

गणना व्यवस्था प्रत्येक मतगणना टेबल पर एक कार्डिंग सुपरवाइजर, एक कार्डिंग असिस्टेंट, एक कार्डिंग स्टॉफ तथा एक माइक्रो ऑब्जर्वर रहेगा। करीब 75 गणनाकर्मी मतगणना सम्पन्न करेंगे।

मतगणना हॉल के भीतर ये सामग्री ले जा सकेंगे: मतगणना हॉल के भीतर पासधारी अभ्यर्थी, निर्वाचन अधिकर्ता, मतगणना अधिकर्ता को कोरा कागज, मतपत्र लेखा प्रारूप 17 सी भाग-1 की प्रति, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रदाय किए गए ईवीएम और वीवीपैट की सूची जो विभिन्न मतदान केन्द्रों में प्रयोग में लाई गई है तथा प्लास्टिक पेन या पेंसिल ले जाने की अनुमति रहेगी। ये सामग्री रहेगी प्रतिबंधित: मतगणना हॉल में मोबाइल फोन, आईपैड, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, कैमरा, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बीडी, सिगरेट और गुटखा प्रतिबंधित रहेगा।

प्रधानमंत्री का आह्वान, देश ही नहीं, दुनिया को नई दिशा देने का प्रयास

केन्द्रीय मंत्री श्री सिंधिया ने अपनी माँ की याद में किया पौध-रोपण



भोपाल/इंदौर (नप्र)। केन्द्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंदौर के कनाड़िया क्षेत्र में हुए वृहद पौध-रोपण अभियान में अपनी माँ स्व. श्रीमती माधवी राजे सिंधिया की याद में पौध-रोपण किया। उन्होंने त्रिवेणी के रूप में बरगद, नीम एवं पीपल के पौधे रोपे। इंदौर में इस अभियान के तहत 51 लाख पौधों का रोपण किया जा रहा है। केन्द्रीय मंत्री श्री सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पर्यावरण संरक्षण के लिये एक पेड़ माँ के नाम लगाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि बीती दो सदी में मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं के लिये प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया है। इस वजह से पूरी

दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग का संकट खड़ा हो गया है। केन्द्रीय मंत्री श्री सिंधिया ने कहा कि सदियों से भारत भूमि, नदियों, पर्वतों और वनों की रक्षा करता आया है। उन्होंने कहा कि एक पेड़ काटना यानी जीवन के एक क्षण के काटने के समान है। अब जरूरत है कि देश का प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक पौधा रोपे और उसकी सुरक्षा का संकल्प लें। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि प्रकृति ने हमें जो सिस्टम दिया है, इसके संरक्षण का दायित्व प्रत्येक व्यक्ति का है। वृहद पौध-रोपण अभियान से इंदौर का ग्रीन कवर बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। पौध-रोपण से हरियाली के साथ भूमि के जल स्तर में वृद्धि

मंत्री श्री विजयवर्गीय और मंत्री श्री सिलावट ने इंदौर में हुए पौध-रोपण कार्यक्रम को किया संबोधित

होगी। मंत्री श्री विजयवर्गीय ने कहा कि जब हम धरती माँ से जीवन जीने के लिये कुछ पाते हैं, तो उसे लौटाने का दायित्व भी प्रत्येक व्यक्ति का है। जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान में इंदौर में 51 लाख पौध-रोपण किया जा रहा है। यह देश के लिये मिसाल बनेगा। इंदौर की पहचान क्लीन सिटी के रूप में देश में होती है। अब इंदौर को ग्रीन सिटी के रूप में भी पहचान दिलाई जायेगी। इंदौर महापौर श्री पुष्पमित्र भार्गव ने कहा कि आज के पौध-रोपण स्थल को स्व. माधवी राजे सिंधिया की याद में उपवन के रूप में विकसित किया जाएगा। कार्यक्रम में स्थानीय सांसद श्री शंकर लालवानी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रीना मालवीय, विधायक श्री रमेश मेंदोला, श्री मधु वर्मा, श्री गोलू शुक्ला सहित बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद थे।

सिंघल आयोग की रिपोर्ट पर भोपाल के अधिकारियों-कर्मचारियों की प्रतिक्रिया

10 आयोग की सिफारिशों के बाद भी नहीं सुधरी विसंगतियां, क्या उम्मीद करें?

भोपाल (नप्र)। जीपी सिंघल आयोग की रिपोर्ट को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। बड़े कर्मचारी संगठनों के नेताओं का कहना है कि कर्मचारियों के वेतन, ग्रेड-पे और पदनाम परिवर्तन जैसे मुद्दे पिछले चार दशक से चल रहे हैं। इनके निराकरण के लिए 10 आयोग-समितियां बनाई गईं। इनमें से कई आयोग ने तत्कालीन कर्मचारी नेताओं के साथ बैठक कर निर्णय लिया और अपनी रिपोर्ट में वह सिफारिश की, पर सरकार ने आज तक उन्हें लागू नहीं किया। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार आयोग-समितियों की आधू-अधूरी सिफारिशें लागू करेगी, तो आयोग-दर-आयोग बनते रहेंगे और विसंगतियां कभी हल नहीं होंगी। इसलिए सरकार को चाहिए कि सिंघल आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करे, कर्मचारी संगठनों के साथ आयोग की सिफारिशों पर मंथन करे और आपसी सहमति से रिपोर्ट को लागू करे, ताकि इन्हीं विसंगतियों को लेकर भविष्य में कोई आयोग बनाने की जरूरत न पड़े।

रिपोर्ट से कर्मचारी संतुष्ट नहीं

ज्यादातर कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने अब तक सिंघल आयोग की रिपोर्ट नहीं देखी है और उन्हें यह भी पता नहीं है कि रिपोर्ट में उनके संवर्ग को लेकर सिफारिश की गई हैं या नहीं। वहीं मप्र लघु वेतन कर्मचारी संघ के नेताओं का कहना है कि उनकी ग्रेड-पे की मांग को रिपोर्ट में तरजीह नहीं दी गई है। ऐसा

ही दूसरे कर्मचारी संवर्गों को लेकर भी हुआ है।

कर्मचारियों की विसंगतियां

लिपिकों के वेतन की विसंगति 1984 से चल रही है। तृतीय श्रेणी में लिपिकों का वेतन पटवारी, सहायक शिक्षक, ग्राम सेवक, ग्राम सहायक, पशु क्षेत्र चिकित्सा



अधिकारी संवर्ग से ज्यादा था। धीरे-धीरे नीचे वाले सभी संवर्गों के वेतन बढ़ते गए और विभाग प्रमुख एवं निचले कार्यालयों में पदस्थ लिपिकों को ग्रेड-पे कम मिलने लगा। वर्तमान में मंत्रालय के लिपिकों को ग्रेड-पे सबसे ज्यादा है।

लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी के ग्रेड-पे में 100 रुपए का अंतर: आज की स्थिति में लिपिक तृतीय श्रेणी के संवर्गों में वेतन में निम्न स्तर पर है। लिपिक और चतुर्थ श्रेणी की ग्रेड-पे में केवल 100 रुपए का अंतर है। राजस्थान में लिपिकों का वेतनमान बढ़ाया जा चुका है।

भोपाल में बुजुर्ग दंपति पर चाकू-रॉड से हमला

पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, थाने में बैठाए रखा; पुलिस कमिश्नर तक पहुंची शिकायत

भोपाल (नप्र)। भोपाल के हबीबगंज थाना इलाके के ईश्वर नगर में रहने वाले बुजुर्ग दंपति पर रिश्तेदारों ने चाकू, रॉड और डंडे से हमला कर दिया। आरोपियों ने बुजुर्ग दंपती का बचाव करने आए बेटे और बेटी को भी पीटा। घटना के बाद शिकायत दर्ज कराने पहुंचे परिवार को पुलिस ने घंटों थाने में बैठाए रखा। बाद में एफआईआर दर्ज की गई।

फरियादी पक्ष ने हबीबगंज थाना पुलिस की शिकायत पुलिस कमिश्नर कार्यालय में की है। विपिन सिंह राजपूत (25) ईश्वर नगर में रहते हैं और किराने की दुकान का संचालन करते हैं। उन्होंने बताया कि 7 जुलाई की रात को दुकान बंद करने के बाद घर के बाहर दोस्त राजू साहू के साथ खड़े थे। तभी पड़ोस में रहने वाला चाचा का बेटा रोहित राजपूत आया। उसके परिवार की और हमारी पुरानी रंजिश थी। रोहित ने इसी रंजिश के चलते मुझे अपशब्द कहना शुरू कर दिया। यह सुनकर पिता दिलीप सिंह राजपूत आए। उन्होंने रोहित को समझाझा देने का प्रयास किया। इस पर आरोपी ने पिता के साथ बदसलूकी की। विरोध करने पर वह अपने घर में गया,



और पिता भगवान सिंह राजपूत, मां संगीता बाई, भाई रितिक, रिपब के साथ चाकू रॉड और डंडे से लैस होकर आया। इसके बाद पिता के साथ मारपीट शुरू कर दी। मैं बचाव करने गया, मुझे भी आरोपियों ने पीटा, यह देख मां अनौता

भोपाल में बीएनएसएस का पहला आदेश

एयरपोर्ट, लालघाटी-करोंद चौराहे तक न ड्रोन उड़ेगा, न लेजर बीम लाइट जलेगी

भोपाल (नप्र)। भोपाल में बीएनएसएस (भारत नागरिक सुरक्षा संहिता-23) का पहला आदेश शुक्रवार को जारी हुआ। प्रमुख जगहों पर निकलने वाले जुलूस में बीम लाइट नहीं चलेगी, जबकि एयरपोर्ट समेत आसपास के क्षेत्र में ड्रोन नहीं उड़या जा सकेगा। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया, आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। बता दें कि इससे पहले धारा 144 के तहत यह आदेश जारी किए जाते थे। अब बीएनएसएस के तहत आदेश जारी किए हैं। एडीएम हिमांशु चंद्र ने यह आदेश जारी किया है।

आदेश में यह

लालघाटी क्षेत्र से संत हिरदाराम नगर (बैरगढ़) तक, लालघाटी से एयरपोर्ट तक, एयरपोर्ट से मुबारकपुर चौराहे और करोंद चौराहे तक के लिए यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। जिसके अंतर्गत किसी भी भवन, मैरेज गार्डन में विवाह एवं अन्य किसी

भी प्रकार के जुलूस के दौरान लेजर बीम लाइट का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। हवाई पटारखे भी नहीं फोड़े जा सकेंगे: लालघाटी क्षेत्र से संत हिरदाराम नगर तक, लालघाटी से एयरपोर्ट तक, एयरपोर्ट से मुबारकपुर चौराहा और एयरपोर्ट से करोंद चौराहे तक किसी भी भवन, मैरेज गार्डन में विवाह एवं अन्य किसी भी प्रकार के जुलूस के दौरान हवाई पटारखे का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं होगा।

इन जगहों पर ड्रोन नहीं उड़ेगा

लालघाटी क्षेत्र से संत हिरदाराम नगर, लालघाटी से एयरपोर्ट तक, एयरपोर्ट से मुबारकपुर चौराहा क्षेत्र तक एवं एयरपोर्ट से करोंद चौराहा तक के क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

आदेश का उल्लंघन पर यह कार्रवाई: इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

प्रदेश में वंचित वर्ग की बालिकाओं के लिये 732 छात्रावासों का हो रहा है संचालन

छात्रावासों में 76 हजार से अधिक बालिकाएं कर रही हैं अध्ययन

भोपाल (नप्र)। प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा सुविधा से वंचित रहने वाली बेघर, अनाथ, शाला से बाहर बालिकाओं के लिये अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये 732 बालिका छात्रावास और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं। इन छात्रावासों में करीब 76 हजार 450 बालिकाएं अध्ययनरत हैं। इन छात्रावासों का संचालन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है।

बालिका छात्रावास

वर्तमान में 324 बालिका छात्रावास संचालित हो रहे हैं। इनमें करीब 23 हजार 100 बालिकाएं अध्ययनरत हैं। बालिका छात्रावास की गतिविधियों में बालिकाओं को वृतिका, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट, लायबेरी एवं उपचारात्मक शिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय: कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय केन्द्र सरकार की मदद से संचालित किये जा रहे हैं, यह विद्यालय उन क्षेत्रों में संचालित किये जा रहे हैं, जहाँ महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है। इन छात्रावासों में 75 प्रतिशत बालिकाएं अनुसूचित जाति, जनजाति,

पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय की हैं। शेष 25 प्रतिशत बालिका अल्पसंख्यक एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाली अनाथ, बेसहारा एवं एकल परिवार से ताल्लुक रखती हैं। चयनित बालिकाओं को कक्षा 8वीं तक की शिक्षा पूरी करने के लिये आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वर्तमान में संचालित 207 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में करीब 33 हजार 250 बालिकाएं लाभान्वित हो रही हैं। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत कक्षा 9वीं से 12वीं के लिये 201 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित हो रहे हैं। इनमें 20 हजार 100 बालिकाओं को अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। छात्राओं को आवासीय सुविधा के साथ भोजन, स्पोर्ट्स, आत्मरक्षा, कैरियर काउंसलिंग और उपचारात्मक शिक्षा की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है।

पलायन छात्रावास

प्रदेश में ऐसे परिवार, जो प्रायः खेती के समय रोजगार की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर पलायन करते हैं। पलायन के समय वे अपने साथ शाला जाने योग्य बच्चों को भी ले जाते हैं।

थाने में नहीं की सुनवाई

विपिन ने बताया कि घटना के बाद थाने पहुंचे। वहां पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, एक घंटे से अधिक समय तक थाने में बैठाए रखा। बाद में बेहद साधारण धाराओं में एफआईआर दर्ज की। हमले में घायल मां और पिता जेपी अस्पताल में भर्ती थे। आरोपी 8 जुलाई को वहां उन्हें धमकाने पहुंचे। इस बात की शिकायत भी थाने में की लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई। 10 जुलाई को मामले की शिकायत पुलिस कमिश्नर के कार्यालय में की। शिकायती आवेदन में पुलिस की लापरवाही की पूरी कहानी लिखी। पुलिस कमिश्नर कार्यालय से थाने फोन गया। इसके बाद आरोपियों को हिरासत में लिया गया।

तत्काल कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार किया

टीआई अजय कुमार सोनी ने बताया कि मामले में तत्काल कार्रवाई की थी। आरोपियों को तलाश कर उन्हें गिरफ्तार भी किया जा चुका है। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर में धाराएं लगाई थीं।

संपादकीय

गुजारा भत्ता- कोर्ट का सही फैसला

सुप्रीम कोर्ट द्वारा तलाकशुदा मुस्लिम महिला को भी पति से गुजारा भत्ता पाने का हक देने के फैसले पर भी सियासत शुरू हो गई है। जबकि यह निर्णय पूरी तरह उन मुस्लिम महिलाओं के हक में है, जो अपने पति द्वारा मनमाने तरीके से तीन तलाक देने के बाद आर्थिक संकट का सामना करती हैं।

जस्टिस बीबी नारगठा और जस्टिस ऑफ़ीस्टन जॉर्ज मसीह की बेंच ने गुजारा भत्ते के खिलाफ एक मुस्लिम युवक की याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपराध प्रक्रिया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 के तहत अपने पति से भरण-पोषण की हकदार है। जस्टिस नारगठा ने अपने फैसले में कहा कि 'महिलाओं को भरण-पोषण अर्थात् गुजारा भत्ता दान का मामला नहीं है, बल्कि विवाहित महिलाओं का मौलिक अधिकार है। यह ऐसा अधिकार है, जो भारत में धर्मान्तरण है और धार्मिक सीमाओं से परे है। यह ऐसा अधिकार है, जो सभी विवाहित महिलाओं के लिए लैंगिक समानता और वित्तीय सुरक्षा के सिद्धांत को और मजबूत करता है।' उन्होंने यह भी कहा कि अब वक आ गया है कि भारतीय पुरुष पत्नी के त्याग को पहचानें। गौरतलब है कि इस मामले में तेलंगाना के युवक अब्दुल ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि उसे तलाकशुदा पत्नी को 20 हजार रुपए महीना गुजारा भत्ता देना होगा। पति ने इस आदेश को तेलंगाना हाई कोर्ट में चुनौती दी। फिर इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। अब्दुल का कहना था कि उसने मुस्लिम कानून के तहत तलाक लिया है और उन पर गुजारा भत्ता का कानून लागू नहीं होता। मुस्लिम परमल लॉ के तहत उसने अपनी पत्नी को जो देना था, उसका भुगतान तलाक के समय कर दिया था। लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि हर धर्म को महिला को समान हक देने का कानून हमारे सिंधान में है। इससे किसी को अलग नहीं किया जा सकता। यदि कानूनी रूप से अवैध तीन तलाक भी दिया गया है तो महिला गुजारे भत्ते की हकदार होगी। वैसे भी अभी तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता मिल ही रहा है। यदि पूर्व पति यह राशि देने की स्थिति में न तो उस राशि का भुगतान वक्फ बोर्ड द्वारा किए जाने का प्रावधान है। इस अहम फैसले के बाद मुस्लिम संगठनों में हलचल मच गई है। जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने संगठन की बैठक बुलाकर कहा कि कोर्ट के फैसले के अध्ययन के बाद आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। कट्टरपंथी मुसलमानों का कहना है कि कोर्ट का ये फैसला शरिया कानून में दखल है और मर्दों के साथ नाईसाफी है। उधर विश्व हिंदू परिषद ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए इसे मुस्लिम महिलाओं के हित में बताया। उन्होंने यह भी कहा कि अब कट्टरपंथी मुसलमान केन्द्र सरकार को उस तरह से ब्लैकमेल नहीं कर सकेगे, जैसा कि उन्होंने शाह बानो केस में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को किया था। उल्लेखनीय है कि 1985 में शाह बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ही फैसला सुनाया था। लेकिन उस वक्त मुसलमानों द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों को जवाब से राजीव सरकार ने 'मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ़ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986' लागू कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कम अपर कर दिया था। राजनीतिक पाटियों ने इस फैसले पर संभल कर प्रतिक्रिया दी है। लेकिन कट्टरपंथी मुस्लिम नेता और मुल्ला मौलवी इस मुद्दे पर सभी मुसलमानों को सरकार के खिलाफ गोलबंद करने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन इससे धुवीकरण और तेज होगा।

नजरिया

प्रो. कन्हैया त्रिपाठी

लेखक भारत के राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी रह चुके हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब में चेयर प्रोफेसर हैं।



नई सरकार गठन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अधिकारिक यात्रा पर हैं। भारतीय संबंध प्रगाढ़ बनाने की यह एक कोशिश है जो बहुत ही मायने रखती है। नरेंद्र मोदी की बतौर प्रधानमंत्री विदेश तीसरी पारी है और विदेशों में इसलिए सम्मान बढ़ा है। जिन देशों में प्रधानमंत्री जा रहे हैं, वहां के नेतृत्व को भी भरोसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं, उसके पीछे उनके देश में उनकी लोकप्रियता है, उनका काम है और उन पर भारतीय जनता का विश्वास है। यह कहा जाये कि भारत की छवि विदेशों में नरेंद्र मोदी ने उत्कृष्ट बनायी है, तो आज यह कोई अतिशयोक्तिपूर्ण बात न होगी।

फिलहाल, इस यात्रा से भारत को जो फायदा होने जा रहा है उसका आकलन तत्काल नहीं किया जा सकता लेकिन आने वाले समय में इसका फायदा नज़र आने वाला है क्योंकि रूस के साथ भारतीय संबंध बहुत पुराने हैं और पुतिन के साथ भी मोदी नेतृत्व वाली सरकार ने मैत्रीपूर्ण संबंध बनाये रखे। इस मैत्रीपूर्ण संबंध का ही नतीजा है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े पैमाने पर उद्देश्यपूर्ण समझौते किये हैं। अब अर रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र और भारत के बीच व्यापार एवं संयुक्त निवेश की परियोजनाओं में और अधिक वृद्धि की संभावनाएं हैं। जलवायु परिवर्तन और निम्न-कार्बन विकास के मुद्दों पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना अब हो सकेगी। कम लागत वाली प्रौद्योगिकियों को विकसित करने हेतु सर्वोत्तम सूचना व सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों का आदान-प्रदान होगा। अनुसंधान की दिशा में दोनों देश व्यापक सहयोग के लिए तत्पर हुए हैं। भूगणित-जियोडसी, मानचित्रकला-कोर्टाग्राफी और स्थानिक डेटा अवसंरचना में ज्ञान एवं अनुभव का आदान-प्रदान होने जा रहा है। व्यावसायिक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण हेतु भी दोनों देश एक साथ कार्य करने के लिए तैयार हुए हैं। वैज्ञानिक एवं शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग होने जा रहा है। संसंधानों एवं डेटा को साझाकर ध्ववीय वातावरण, ध्ववीय क्षेत्रों में लॉजिस्टिक्स, संयुक्त रूप से बौद्धिक व अनुसंधान साझेदारी, अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं में समुचित भागीदारी तो बढ़ेगी ही। साथ ही क्षमता निर्माण के जरिए मानव उपयोग हेतु उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। वाणिज्यिक प्रकृति के नागरिक कानून से संबंधित विवादों के निपटारे हो सकें, इस पर सुविधाजनक प्रणाली बनाने हेतु दोनों देश राजी हुए हैं। निवेश संबंधी सहयोग को प्रोत्साहन मिलने जा रहा है साथ ही भारतीय बाजार में रूसी कंपनियों के निवेश को भी मौका अब भारत में मिलेगा। द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए दोनों देश एकमत हैं।

मोदी की रूस यात्रा से भारत को मिलेगी गतिशीलता

भारत के लिए यह गौरव की बात है इस देश के प्रधानमंत्री को 300 साल पहले शुरू किये गए रूस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ‘द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल’ से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नेता हैं जिन्हें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सम्मानित किया है। उन्हें यह पुरस्कार भारत-रूस संबंधों को बढ़ावा देने और द्विपक्षीय योगदान के लिए क्रेमलिन के सेंट एंड्रयू हॉल के एक विशेष समारोह में दिया गया। किसी देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित होना बहुत ही विशिष्ट बात है, वह भी जब भारत के संबंध

व्यापार संबंधन हेतु व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों की आवाजाही बढ़ेगी।

भारत के लिए यह गौरव की बात है इस देश के प्रधानमंत्री को 300 साल पहले शुरू किये गए रूस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ‘द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल’ से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नेता हैं जिन्हें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सम्मानित किया है। उन्हें यह पुरस्कार भारत-रूस संबंधों को बढ़ावा देने और द्विपक्षीय योगदान के लिए क्रेमलिन के सेंट एंड्रयू हॉल के एक विशेष समारोह में दिया गया। किसी देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित होना बहुत ही विशिष्ट बात है, वह भी जब भारत के संबंध पूर्ववर्ती सरकारों के साथ बहुत मधुर रहे हों, उन्हें यह पुरस्कार न दिया गया हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पुरस्कार से सम्मानित हों, तो यह बात काफी मायने रखती है। भारतीय प्रधानमंत्री की ओजशी आत्मशक्ति उनके भारतीय जन में विद्यमान है इसलिए रूस की यात्रा में वह भारत में हो रहे बदलाव को भी रेखांकित कर भारतीय कार्यशक्ति को भारतीय मूल के नागरिकों के बीच रखते हैं और, और अधिक विश्वास से भर जाते हैं। उन्होंने कहा भारत कैसे बदल रहा है? भारत बदल रहा है, क्योंकि भारत अपने 140 करोड़ नागरिकों के सामर्थ्य पर भरोसा करता है, गर्व करता है। भारत बदल रहा है, क्योंकि 140 करोड़ भारतीय अब विकसित देश बनने का सपना संकल्प लेकर के पूरा करना चाहते हैं। हिन्दुस्तान पूरा मेहनत कर रहा है, हर किसान कर रहा है, हर नौजवान कर रहा है, हर गर्वब कर रहा है। प्रधानमंत्री की सबको साथ लेकर चलने और उनके कार्यों को श्रेय देने की जो कला है वह निःसंदेह पूरे विश्व को अब पता चल गया है। देश चाहे जो भी हो, भारतीय मूल के लोग उन्हें सुनते हैं और उनके स्वर अभिव्यक्त विचारों के साथ संकल्प लेकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए तत्पर भी हो रहे हैं, यह रूस की आधिकारिक यात्रा



में साफ-साफ लिखा।

प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया इस यात्रा के दौरान कि दशकों से भारत और रूस के बीच जो अनोखा रिश्ता है, उसका कायल रहा हूं। रूस शब्द सुनते ही हर भारतीय के मन में पहला शब्द आता है। भारत के सुख-दुख का साथी। भारत का भरोसेमंद दोस्त। हमारे रूसी मित्र इसे दुजबा कहते हैं, और हम हिंदी में इसे दोस्ती कहते हैं। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत-रूस मैत्री को खुद काफी तरजीह दी है और साथ ही रूसी राष्ट्रपति प्रेसीडेंट पुतिन के कार्यों, नेतृत्व व साझादारी की सराहना की है। दो दशक से ज्यादा समय तक भारत के प्रधानमंत्री का दायित्व निभा चुके नरेन्द्र मोदी 10 सालों में में छह बार रूस की यात्रा के लिए गए हैं और सबसे अहम बात यह है कि पुतिन और मोदी एक दूसरे से 17 बार मिल चुके हैं। ये सारे मेल-मिलाप न केवल विश्वास को बढ़ाये हैं बल्कि एक दूसरे के भीतर सम्मान को भी बढ़ाये हैं जिसे हम यूं भी देख सकते हैं कि राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से अभिनंदन किया है। विश्वास की एक कड़ी अभी रही है जब भारत यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ और भारतीय छत्र जो रूस या यूक्रेन में फंस गए, संवर्ष के बीच फंसे उन बच्चों को राष्ट्रपति पुतिन वापस भारत पहुंचाने में मदद की। विश्वास इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि अब राष्ट्रपति पुतिन और

मुद्दा

राजीव खंडेलवाल

(लेखक, कर सलाहकार एवं पूर्व बैतूल सुधार न्याय अध्यक्ष हैं)

‘बाबा प्रधान देश’ भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के ‘हाथरस’ (जो पूर्व में भी, सितम्बर 2020 में गैंगरेप-हत्या के कारण विश्व प्रसिद्ध हो चुका है?), में मानव मंगल मिलन (सत्संग, धार्मिक समागम) के दौरान भगदड़ मचने से 123 व्यक्ति अकाल मृत्यु ‘काल के गाल’ में समा गये। जिस ‘काल’ को नियंत्रित करने का दावा संत के वेश में सूरजपाल जाटव ऊर्फ विश्व हरि उर्फ नारायण हरि करता रहा। घटना के बाद से ही संपूर्ण मीडिया चाहे फ़िट, इलेक्ट्रानिक या सोशल मीडिया हो, बड़-चक्कर इस बहुरूपिये बाबा की कुंडली को खोलकर चिन्न-चिन्ना कर हम जनता को बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। धूर्त बाबा का इतिहास क्या था? जो एक छेड़खानी के आरोप में बर्खास्त सजायाफ्ता हवलदार नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा था। यद्यपि अदालत के आदेश से वह पुनः नौकरी में बहाल भी हो गया था। जेल से छूटने के बाद उसने वीआरएस लेकर ‘भोले बाबा’ बनकर लोगों को ठाने, पाखंड और यौन शोषण के कार्यक्रम में ‘सत्संग’ के साथ लग गया। साधु संत तो वह होता है जो ‘करे तो डरे, न करे तो भी खुदा के कहर से डरे’। लेकिन ये बाबा तो कर के भी नहीं डरते। कोई दान दक्षिणा चढ़ना इत्यादि न लेने का दावा करने वाले बाबा के देश में अनेक बड़े-बड़े आश्रम है तथापि राजस्व रिकॉर्ड पर उनके स्वाभिमन के बाबत सुनिश्चित जानकारी नहीं है। यद्यपि बाबा इंटरनेट पर लोकप्रिय नहीं है तथापि जमीनी स्तर पर उनके भक्तों की संख्या लाखों में है।

धूर्त, प्रंचं गिरी व यौन शोषण का आदी सूरजपाल एक दिन में ही अपराधी, व्यक्तिचारी, जादू-टोटेका, भूत भगाने वाले, ढोंगी बाबा नहीं बन गया? परन्तु धन्य है हमारे देश का मीडिया, जिसे उस घटना घटित होने तक पता ही नहीं चला कि सन्यासी के वेश में

बाबा एक अपराधी है। ऐसे ही बाबाओं के कारण हिन्दू समाज बदनाम होता रहा है। हिन्दू समाज जो हर ‘कमली वाले को फकौर’ समझ लेता है और जहां ऐसे सजायाफ्ता साधु-संतों के अंधभक्तों की संख्या में और उनके साम्राज्य में कोई खास कमी हुई हो, ऐसा जान नहीं पड़ता है, न ही महसूस होता है।

आखिर ऐसे बाबाओं को प्रोत्साहन कैसे मिलता है? किससे मिलता है? जिस कारण से बाबागिरी या सत्संग एक बड़ा “उद्योग” हो गया है। इसका एक बड़ा कारण राजनीति और बाबाओं के बीच बड़ा अटूट अंतरंग संबंध चला आ रहा है। हर ऐसे बाबाओं के साथ देश के प्रमुख राजनेताओं के चाहे किसी झुंड के तले हो, अंतर-मुखी परिचय की फोटों, सिर नवाये, आशीर्वाद देते हुए मिल जायेंगी। इसका एक मात्र कारण यह है कि नेताओं के प्रभाव व आकर्षण से बाबाओं को भी अपना साम्राज्य गरीब अनपढ़ जनता के बीच बढ़ाने का अवसर मिल जाता है। वहीं दूसरी ओर बाबाओं के अंधभक्तों की लम्बी चौड़ी फौज के कारण उनके वोट मिलने की उम्मीद में नेताओं की लाईन दर्शन, आशीर्वाद के लिए लगी रहती है। इस प्रकार नेता और बाबा दोनों परस्पर सहजीविता (सिम्बायोसिस) के सिद्धांत के माध्यम से अपनी अपनी दुकान चलाते रहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण गुरमीत सिंह उर्फ राम रहीम का है, जहां राज्य सरकार से भारतीय दंड संहिता के सबसे कठोरतम अपराध में सजा भुगत रहे बाबा को बार-बार चुनाव के समय पैरोल, ‘फरलो’ मिलती रही है। बाबा व नेता एक दूसरे के लिए कितने ‘पूरक’ होते है, यह इस घटना से भी सिद्ध होता है। जहां किसी भी पार्टी के किसी भी राष्ट्रीय और महत्वपूर्ण नेता ने सामने आकर बाबा की गिरफ्तारी की मांग स्पष्ट रूप से अभी तक

नहीं की हैं, सिर्फ मायावती को छोड़कर। इसका भी कारण स्पष्ट है। दलित वोट बैंक में बाबा की घुसपैठ होने के कारण मायावती नहीं चाहती है कि उनके दलित बैक में गांव किसी भी नेता या धार्मिक बाबा की दखलंदाजी जी हो। किसान नेता राकेश टिकैत ने तो बाबा की टीम को क्लीन चिट देते हुए घटना को मात्र ‘हादसा’ बता दिया। एसआईटी को यह नहीं दिखा कि बाबा के चरणों की धूल लोगों के जीवन की राख में परिवर्तित हो गई। हादसा का प्रारंभ तभी हुआ जब लोग बाबा के चरणों की धूल पाने आव्हान पर दौड़ पड़े। हादसा होने पर घटना की उच्च स्तरीय जांच, मजिस्ट्रेट जांच, एसआईटी जांच, न्यायिक जांच की घोषणा कर दी जाती है। कहा जाता है कि घटना के पीछे भी की षड्यंत्रकारी है, उन्हें हर हालत में सामने लाया जाएगा। जवाबदेही तय की जावेगी। जांच प्रक्रिया चालू है। कानून अपना काम कर रहा है। मामला बेहद संवेदनशील है। राजनीति मत करो! यह समय राजनीति का नहीं है, बल्कि पीड़िता, भुक्तभोगियों के साथ खड़े होने का है। ‘मरहम’ के रूप में “मुआवजा” की भी घोषणा की जाती है, जो भुक्तभोगियों की आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए नहीं बल्कि राजनैतिक नफा-नुकसान की दृष्टि से की जाती है? नौकरी देने की घोषणा कर दी जाती है।

प्रस्तुत प्रकरण में ही दूसरों को राजनीति न करने की सलाह देने वाले स्वयं राजनीति कर रहे हैं। मुख्य सेवादार व आयोगक देव प्रकाश मधुकर को मुख्य अभियुक्त बिना किसी भी पार्टी के किसी भी राष्ट्रीय और प्रमुख अभियुक्त इसलिए अभी तक नहीं बनाया गया कि कबूतर रूपी बाबा हमेशा

राजनीति के कुएं को बसेरा बनाते हैं’। बस “जांच चल रही है”। जांच में तथ्य पाये जाने पर तत्नुसार कार्रवाई की जाएगी? बाबा अपराधी नहीं है, तो वह घटनाओं के तुरंत बाद “गायब” क्यों हो गया है। इस मामले में एसडीएम सहित 6 सरकारी मुलाजिम लिलंबित किए गए हैं। घटना के जिम्मेदार “भोले बाबा” वास्तव मे उतने भोले नहीं है, मीडिया को छोड़कर समस्त तंत्र राजनैतिक और पुलिस तंत्र सहित जितना उसे भोले व भले बाबा बनाने व बतलाने का भरकम सफल प्रयास कर रहा है। उसका वकील उसे सोची समझी साजिश बता रहे हैं। तारीफ की बात तो यह है कि बिना कोई साक्ष्य तथा तथ्य पाए एसआईटी भी अपनी रिपोर्ट में इस संभावनाओं को नकार नहीं रही है। आरोपी बनाना तो दूर अभी तक सूरजपाल से किसी भी जांच एजेंसी ने पूछताछ करना तो दूर बातचीत करना भी मुनासिब नहीं समझा है? कारण स्पष्ट है। दलित जाटव जाति से बाबा का होना राजनीतिक दलों के लिए एक वोट बैंक है! एक तथ्य यह भी है कि वर्तमान में बाबा के खिलाफ 5 अपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। परंतु कार्रवाई शायद ठन-ठन गोपाल?

80 हजार लोगों की अनुमति के साथ 2.5 लाख से अधिक जनता का सत्संग में आने की कोई पूर्व सूचना इनपुट आई. बी., एल. आई. यू. (स्थानीय अभिसूचना इकाई) व अन्य जांच एजेंसीज को न होना, क्या पुलिस प्रशासन का बुरी तरह से असफल होना नहीं है? देश की “कृपमंडूकता” का यह घटना एक वीभत्स उदाहरण है। आज भी बाबा के निवास के घर की चौकट पर अंधभक्त लोग इतनी बड़ी “वारदात”, जिसे पुलिस प्रशासन ने हादसा करार कर दिया है, होने के बावजूद मत्था टेकने जा रहे हैं।

कटाक्ष

प्रीतम लखवाल

देश में इस समय भयंकर चिंता, चिंतन और मंथन के साथ मनन का माहौल है। इस ‘भयंकर’ कार्य में पक्षी परेशान हैं तो वि-पक्षी भी। मैं इस पर बाद में आऊंगा, लेकिन इससे पहले एक और चिंतनीय खबर पक्षी विज्ञानियों ने बहुत पहले सुना दी थी कि देश से कौवे विलुप्त हो रहे हैं। इसकी पुष्टि के लिए लोगों ने एक नया तरीका ईजाद किया हुआ है, लेकिन उसके लिए कम से कम बारिश के मौसम को खत्म होने का इंतजार करना पड़ता है। वह भी गणेशोत्सव के बाद यानी श्राद्ध पक्ष का। वास्तव में श्राद्ध पक्ष में बहुत मनाने पर भी कौवे छातों पर नहीं आते। उनका भाग यू ही धूप में सूख जाता है और...। नगरों और महानगरों में तो अब कांव-



कांव सुनाई ही नहीं देती। एक अदद सवाल उठता रहता है कि आखिर कौवे गए कहां? उनका शहरों, नगरों और महानगरों से बैर क्या है? इस पर पक्षी विज्ञानी भी चुप हैं। वे चूप क्यों हैं, क्योंकि उन्हें ही नहीं पता कि बड़ी तादात में उड़ने वाले, छत पर बैठकर किसी मेहमान के आने की सूचना देने वाले, अपनी कर्कश आवाज में अपने किसी साथी के गुजर(सर) जाने के बाद पूरा आसमान सिर पर उठाकर पूरे समाज को इकट्ठा करने वाले कौवे इतने बेरहम क्यों हो गए कि अब बुलाने पर भी नहीं आते। नहीं तो पहले तो उन्हें भगा-भगा के हलकान हुए जाते थे। घर के एक बुजुर्ग(जिसका टाइटम पास नहीं होता था)की स्पेशल ड्यूटी इस कागा भगाओ अभियान में लगा दी जाती थी और वह विश्वास की लाठी लिए आंगन या छत पर बैठा रहता था।

हालांकि गांव अभी भी खुश किस्मत हैं कि कुछ कौवे वहां

कान तो अपने हैं और सलामत भी

अपनी कांव-कांव करते रहते हैं। गांवों में पेड़ों की विरासत संरक्षित है शायद, इसलिए वहां कांव-कांव है। अभी-अभी एक महान संत ने बहुत ही उम्य प्रसंग सुनाया- ‘लोग कहते हैं कि कौवा कान ले गया और सब कौवे के पीछे भागने लगते हैं, लेकिन कोई कान नहीं देखात कि वह अपनी जगह है या नहीं’। आजकल राजनीति में भी यही हो रहा है। कोई कहता कुछ है और लोग कह देते हैं कि कौवा कान ले गया। बस लोग उसी झूठे कौवे के पीछे भागने में गोल्ड मैडल जीतना चाहते हैं। अब सवाल यह था कि विलुप्त होकर कौवे गए कहां? तो उस भविष्यदृष्टि भरे ने धीरे से मेरे कंधे पर थपकी

देकर कहा कि वे सब अपना नश्व शरीर छोड़ स्थूल रूप में राजनीति में आ गए। इनमें से अधिकांश को पक्षी(सत्ताधारी) ने मोहपाश में बांध रखा है तो कुछ विपक्षी गुट या दल में चले गए। बस यहीं इनकी फजीहत हो रही है। वो छत की कांव-कांव अब उसी छत पर लगी एल्युमिनियम की छतरी से होती हुई सेंटअप बॉक्स में घुस रही है और पक्षी दल चिन्ना रहा है कि कौवा कान ले गया। विपक्षी कह रहे हैं कि तुम्हारे कान तो सलामत हैं तो फिर सुनते क्यों नहीं।

इस गंभीर मुद्दे पर कैलाश पर्वत पर बैठे काकभुशुंड़ जी का आह्वान किया गया कि बताओ विलुप्त होते कौवे भी कहीं कान ले जा सकते हैं। वे मुस्कुरा उठे और ‘हरि हाथ से मांखन रोटी ले जाने के दृश्य के परीक्ष बैक में चले गए।’ इधर, लोग अभी भी कौवे के पीछे भाग रहे हैं और कान अपनी जगह सलामत हैं।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबन्धु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

संपादक - उमेश त्रिवेदी

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)

RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923, Ph. No. 0755-2422692, 4059111 Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। उनसे समाचार पत्र का सम्बन्ध होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

पूरन सरमा

लेखक व्यंग्यकार हैं।

चमचागिरी का गुण आज की आवश्यकता बन गया है। मैं खुद इस गुण को मुकुंद मानता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों अभी तक चमचा बन नहीं पा रहा हूँ। दफ्तर में पूरा काम समय पर करने के बावजूद मुझे अप्सर स्टाइट एलीफेंट मानता है। जबकि सच यह है कि सफेद हाथी वह स्वयं है। सोरे दिन स्टैनो से बतियाना और उसके साथ कॉफी-चाय पीने के अलावा वह करता ही क्या है? हमेशा गोपनीय रिपोर्ट खराब जाने से मेरे प्रमोशंस भी ठगड में लगा दिये गये हैं। जबकि जो काम के अलावा और सब कुछ करते हैं, उनके धड़ाधड़ प्रमोशन हो रहे हैं। हालांकि वह भली प्रकार से जानता है कि मैं काम का आदमी हूँ इसलिए तो वह मेरा ट्रांसफर नहीं करवाता। परन्तु मेरी आदमी चमचागिरी की नहीं होने के कारण मैं निरंतर पिछड़ रहा हूँ। दरअसल वो चापलूसों और चापलूसी को पसंद करता है। वो हमेशा सर आप कितने काइंड नेचर के हैं, आप सबका ध्यान रखते हैं, आपके बच्चे की फीस जमा करा आऊं, आप कहें तो घर सब्जी-फल रखा आऊं, सर

गुणीजनों का गुण है चापलूसी

आपका जैसा इंसान आज के जमाने में मिलना कठिन है, सर आपने कभी किसी का बुग्रा नहीं किया जैसे जुमले रात-दिन सुनना चाहता है। मुफीद मानने के बावजूद भी मैं चमचागिरी को नहीं अपना सका, इसको मुझे खेद तो है लेकिन खुबुरी के अपने मजे हैं, जिसके मद में चूर मैं अपने आपको सबसे अलग कर लेता हूँ। मोहल्ले की विकास समिति के अध्यक्ष कई बार मुझसे कह चुके कि मैं उनसे मिला कदां। एक बार तो उन्होंने साफ़तौर मुझसे कहा भी कि यार पता नहीं तुम किसी मिट्टी के बने हो। अपने आपको अफ़लातून समझते हो। इसका प्रचार उन्होंने पूरे मोहल्ले में कर दिया है, जिससे मैं वहां भी अलोकप्रिय हो गया हूँ। मोहल्ले वाले मुझे घणघुड़ी करते हैं। जबकि मैं न किसी को अन्धता हूँ, न सताता हूँ लेकिन मेरी जान के दुश्मन बन गये हैं लोग। चमचागिरी में एक तरह अपने आपको गिराना होता है, जो मैं नहीं कर पाता हूँ। पत्नी भी मेरे स्वाभाव को लेकर कहती रहती है कि मोहल्ले में बान्धकर रखो। सभी से मिलो-जुलो, हमारे काम कैसे होंगे। मेरी पत्नी से मोहल्ले की ओरते कहती रहती हैं कि आपके ‘वो’ तो अलग ही हैं, पता नहीं आपकी (पत्नी की) उनसे कैसे पटती होगी।



थोड़ा लिखने-पढ़ने का शौक है तो लेखक भी खिंचे-खिंचे रहते हैं। वे एक-दूसरे से मेरे गर्वोच्चत होने की बात करते हैं। किसी सभा-संगोष्ठी, लोकार्पण, सम्मान समारोह में न जाने से अब लोगों ने आमंत्रण देना ही बंद कर दिया है। राज्य अकादमी मुझसे

जूनियर्स का सम्मान इसी चापलूसी निपुणता गुण के कारण कर चुकी है, लेकिन मेरा हमेशा अपमान ही होता है। सम्पादकों में भी मैं अलोकप्रिय हूँ। उनका कहना है कि न मिलना न जुलना, फिर रचनाओं का प्रकाशन किस आधार पर करें। सच कहूँ तो चमचागिरी के गुण अभाव के कारण मेरा हर क्षेत्र में नुकसान हो रहा है, लेकिन मैं कोशिशों के बावजूद भी अपना मूल स्वभाव अब बदल पा रहा हूँ। इसके अभाव में यों कहा जा सकता है कि मैं असामाजिक प्रणि होकर रह गया हूँ। मुझे कोई धास नहीं डालता, लेकिन मैंने पता नहीं कौनसे जीवन जीवन मृत्यों को चुन लिया है, जिससे नुकसान ही नुकसान हो रहा है। मेरे घर कोई आता नहीं और मैं किसी के घर जाता नहीं, अब आप ही बताइये इससे गुजारा होगा कैसे? काश, मैं भी चापलूस बन पाता, कई बार सोचता हूँ। आज के युग में बिना चमचागिरी के कहीं दाल नहीं गूँथे। इसलिए ज्यादातर लोगों ने अपने तमाम स्वा्थं पूरे करने का साधन बना लिया है। चापलूसी की माया अद्भुत और अपरम्पार है। इसलिए इसे तत्काल अपनाइये और अपना जीवन सुखी बनाइये। गुणीजनों का गुण है चापलूसी आजकल।

मुद्दा

डॉ. ज्योति सिडाना



भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में समता को और लैंगिक आधार पर भेदभाव न किए जाने को अनिवार्य बताया गया है। इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में महिला सुरक्षा, सम्मान, विकास व भेदभाव से बचाव के प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। संविधान महिलाओं को न सिर्फ समानता का अधिकार देता है, बल्कि सभी राज्यों को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक प्रावधान करने का भी निर्देश देता है। संविधान लागू होने के इतने वर्षों बाद भी जब जेंडर गैप रिपोर्ट जारी होती है तो कुछ और ही सच्चाई सामने आती है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत 146 देशों की सूची में 129वें स्थान पर आ गया है जबकि पिछले साल भारत 127वें स्थान पर था। सोचने का विषय है कि आखिर ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो यह गैप घटने के बजाय बढ़ता जा रहा है। शुरूआती दौर में लेखिका मेरी वोल्स्टनक्राफ्ट ने सामाजिक ढाँचे की आलोचना करते हुए कहा था कि स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखा गया, वे सार्वजनिक जीवन में भी अनुपस्थित रहती हैं, अतः स्त्रियों को तार्किक मनुष्य मानते हुए स्त्री-पुरुष में बुनियादी समानता स्थापित करने के प्रयास करने चाहिये। वहीं जॉन स्टुअर्ट मिल भी स्त्री अधिकारों का समर्थन करते हुए कहते हैं कि स्त्री-पुरुष का संबंध आधिपत्य के बजाय सहयोग पर आधारित होना चाहिये। उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा, नागरिकता तथा संपत्ति में समान अधिकार का भी समर्थन किया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि समाज की आधी आबादी होने के बावजूद महिलाएँ हमेशा से मूलभूत अधिकारों से वंचित रही हैं। 21वीं सदी में महिलाओं की स्थिति में अनेक बदलाव हुए हैं जिन्हें नकारा नहीं जा सकता जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सेना, सार्वजनिक क्षेत्र, विभिन्न प्रकार के रोजगार अवसर इत्यादि में महिलाओं की सहभागिता हुई है। लेकिन यह भी तथ्य है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की संख्या में भी दुगुनी-तिगुनी वृद्धि हुई है। क्या यह कहा जा सकता है कि महिलाओं की प्रगति और उनके विरुद्ध होने वाले अपराधों की दर में कोई सकारात्मक सहसंबंध है? क्योंकि



महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति बढ़ती जागरूकता, निर्णय लेने की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वायत्ता, संपत्ति में समान अधिकार, ऐसे पक्ष हैं जिन्होंने पितृसत्तात्मक समाज के सामने चुनौती को उत्पन्न किया है। लेखिका जर्सिंता केकेट्ट ने अपने कविता संग्रह में लिखा कि अ से अनार लिखा उन्होंने कहा आह कितना सुंदर, आ से आम लिखा उन्होंने आम के गुण गाए लेकिन जब अ से अधिकार लिखा तो वे भड़क गए। उनकी इन पंक्तियों से स्पष्ट होता है कि जब तक महिलाएं दमन और आधिपत्य को स्वीकार करती हैं तब तक वे सभ्य और संस्कारी मानी जाती हैं और जैसे ही वे अपने अधिकार या अपने विरुद्ध होने वाले दुर्व्यवहार के लिए आवाज उठाती हैं उन्हें चरित्रहीन घोषित कर दिया जाता है।

विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट के अनुसार भारत उन देशों में

शामिल है जहां आर्थिक लैंगिक समानता सबसे कम है। अर्थात् यहाँ अनुमानित अर्जित आय में 30व से कम लैंगिक समानता दर्ज की गई है। पिछले वर्ष के 127वें स्थान से 129वें स्थान पर गिरावट का कारण शैक्षिक उपलब्धि और राजनीतिक सशक्तिकरण में आयी कमी को माना गया है। भारत महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के मामले में 65वें स्थान पर है और श्रम-बल भागीदारी दर पर 134वें और समान काम के लिए समान वेतन पर 120वें स्थान पर है जो पुरुषों और महिलाओं के बीच आर्थिक असमानताओं को दर्शाता है। अगर इसी गति से समानता की और बढ़ते रहे तो पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में लगभग 134 साल और लगेंगे, जो कि समग्र विकास की राह में बड़ी बाधा बन सकता है।

देखा जाए तो त्रेता और द्वापर युग में भी कल युग जैसे अनेक उदाहरण मिलते हैं द्रोपदी को भी उनके अपने ही परिजनों ने लज्जित किया था और सीता को भी अपनों के द्वारा ही घर त्यागने का दर्श झेलना पड़ा था। जब राम को वनवास जाने का आदेश मिला तो सीता ने उनके साथ जाना चुना और जब सीता को देश निकाला दिया गया तो राम उनके साथ क्यों नहीं गए। सावित्री आपने पति सत्यवान को बचाने के लिए यमराज के पीछे-पीछे चल दी लेकिन ऐसा कोई उदाहरण इतिहास में भी नहीं मिलता जिसमे पुरुषों ने महिलाओं के लिए कोई त्याग किया हो। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि लैंगिक असमानता तो सृष्टि के प्रारम्भ से चली आ रही है। हाँ, इतना जरूर है कि पहले महिला अपने अधिकार नहीं जानती थी और न ही उनके विरुद्ध आवाज उठाती थी लेकिन आज की शिक्षित और

आत्म निर्भर महिला ऐसा करने लगी है। कुछ वर्ष पूर्व हुआ मी-टू आन्दोलन इस बात का एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है।

समाज की अनेक घटनाएं पुरुष सत्तात्मक समाज के विरोधभासी चरित्र को उजागर करती हैं जैसे विवाह के लिए जीवन साथी का चयन करते समय तो धर्म और जाति को बहुत महत्व दिया जाता है, उसी तरह किसके हाथ का बना खाना खाना है और किसके हाथ का नहीं, यह भी ध्यान रखा जाता है लेकिन महिला के साथ दुर्व्यवहार या शारीरिक शोषण करते समय इनमे से किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस धर्म या जाति की है, या किस आयु की है (3 माह की बच्ची है या 80 वर्ष की बुजुर्ग), विवाहित है या अविवाहित, ऐसा क्यों। महिलाओं के साथ हिंसा या शोषण के मामलों में पवित्रता-अपवित्रता के मूल्य हाशिए पर क्यों चले जाते हैं। यदि समाज में परिवर्तन की दर यही रही तो रिपोर्ट में सामने आए आंकड़ों के अनुसार महिला और पुरुषों में समानता लाने के लिए अभी 134 साल और लगेंगे। पहले ही बहुत देर हो चुकी है इस लैंगिक असमानता के कारण समाज अनेक जोखिमों से घिरा हुआ है अब और देर करने कई गुंजाइश नहीं बची है।

स्वामी विवेकानंद उन शास्त्रों की आलोचना करते हैं जो स्त्रियों को ज्ञान प्राप्ति की अधिकारिणी नहीं मानते। उनका मानना था कि देश की सम्पन्नता इस बात पर निर्भर करती है कि स्त्री-पुरुष के साथ समानता का व्यवहार किया जाए। स्त्री भी उतनी ही साहसी होती है जितना कि पुरुष। इसलिए वे मानते थे कि नारी को भी योग्य, सक्षम और कामकाजी बनाना आवश्यक है क्योंकि देश के आर्थिक विकास में दोनों के उत्तरदायित्व समान है। यह कहा जा सकता है कि महिलाओं को राजनीतिक अधिकार दिए बिना सामाजिक व्यवस्था में सुधार संभव नहीं हो सकता और सामाजिक व्यवस्था में बदलाव हुए बिना उनका आर्थिक सशक्तीकरण सही अर्थों में आकार नहीं ले सकता। और इन सबको वास्तविकता के धरातल पर उतारने के लिए गाँधी जी के सुझाव पर अमल करना जरूरी है कि समाज का सकारात्मक परिवर्तन व्यक्ति के हृदय परिवर्तन से ही संभव है।

दृष्टिकोण

बादल सरोज

लेखक लोकजतन के संपादक हैं।



अभी तक देशों के अपने राष्ट्रीय पशु, पक्षी, पेड़, पर्वत, झंडे और दीगर प्रतीक चिन्ह होने के रिवाज प्रचलन में हुआ करते थे। मोदी राज में इनमे खूब इजाफ़ा हुए हैं , कई कई नयी चीज़ें जुड़ी हैं। इन्ही में से एक है राष्ट्रीय विवाह, जो मार्च से शुरू हुआ है और अभी तक है कि चल ही रहा है। इसकी बेसुरी धमाधम शुरू हो चुकी है और गूँज-अनुगूँज उत्तरोत्तर तेज से तेजतर होने वाली है। कोई भ्रम न रह जाए इसलिए अम्बानी की अपनी सरकारों ने इसे बाकायदा सूचना निकाल कर एक सार्वजनिक (पढ़ें राष्ट्रीय) आयोजन का दर्जा दे दिया है। देश की वाणिज्यिक राजधानी मानी जाने वाली मुम्बई में 12 जुलाई से 14 जुलाई तक घोषित रूप से दफ्तर, बाजार यहाँ तक कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) बंद रहेगा। शादी के लिए तैयार महल और उसमे आये मेहमानों के ठहरने की जगहों की कई किलोमीटरों की परिधि में आने वाली सड़कें भी इंडिया डैट इज भारत के नागरिकों के लिए बंद कर दी गयी हैं। इसमें खर्चा कितना होगा इसका अंदाजा भी लगाना सामान्य इस्तेमाल में लाये जाने वाले कैलकुलेटर्स को जाम कर सकता है ; एक मोटा अनुमान इस शादी के पहले हुए दो शादी पूर्व आयोजनों- प्री वेडिंग सेरेमनी - को देखकर लगाने की कोशिश की जा

सकती है। जामनगर के जंगल में मंगल की तरह मार्च महीने के तीन दिनी समारोह में 1259 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। 29 मई से 1 जून तक हुयी दूसरी प्री-वेडिंग 7500 करोड़ रुपयों के पांच तारा आलीशान पानी के जहाज 'कूज' पर 4380 किलोमीटर तक समन्दर पर चली ; इटली से जेनेवा, रोम से फ्रांस कहीं लंच कहीं डिनर कहीं ब्रेकफास्ट करते हुए यह कान्स तक पहुंची। इसमें शामिल हुए दुनिया भर से बुलाये गए कोई 800 मेहमान इस ऐश्वर्य के पर्याय जल-महल के जिन कमरों- रईस कमरों में नहीं रहते, वे उन्हें सुइट कहते हैं - उन एक एक का किराया ही दसियाँ लाख रुपयों में था। इसमें जामनगर से दो गुने से भी कहीं ज्यादा के खर्च की खबर है। मगर ऐसा लगता है जैसे अम्बानी ने वैभव की अश्लीलता की अब तक की सारी हद्दें लांघने और मनुष्यता को लजाने वाली फिजूलखर्ची के दिखावे की हवस को बढ़ते जाने की टान ली है। मुम्बई में होने जा रही इस शादी में, जिसे अम्बानी की सरकारों ने लगभग राष्ट्रीय समारोह का दर्जा दे दिया है, इसी मनोरोग के तीसरे आयाम की फूहड़ता दिखाई जा रही है। इस शादी में बुलावे के लिए भेजा गया निर्मंणग कार्ड ही प्रति कार्ड 7 लाख रुपये का है। इस बारे में ज्यादा विस्तार से शादी के ट्रेडर - टीजर के पहले मार्च में 'जामनगर में वैभव की अश्लीलता और सेंट जी के चिड़ियाघर में बदलता भारत' शीर्षक से लिखा जा चुका है ; इन 4 महीनों अंतर सिर्फ यही

आया है कि अब भारत सचमुच में सेंट जी के चिड़ियाघर में बदल चुका है। जिस देश में खुद उसके प्रधानमंत्री के दावे के हिसाब से 80-85 करोड़ लोग सरकार के 5 किलो राशन और हजार डेढ़ हजार रुपयों की बाट जोहते इतने हताश हो गए हैं कि किसी भी चिरकुट बाबा के यहाँ बीसियाँ हजार की भीड़ बनाकर भगदड़ में मौत के मुंह में जाने की जोखिम उठा रहे हैं। वास्तविक जीवन में कोई उम्मीद न देख काल्पनिक समाधान हासिल करने के लिए अंधविश्वासों की गहरी खाई में छलांग मारने को भी तत्पर हुए जा रहे हैं। ऐसे देश में इतनी विपुल मात्रा में धन का पानी की तरह बहाया जाना किसी भी सभ्य समाज के लिए क्षोभ और लज्जा का विषय है, एक राष्ट्रीय अपराध है। ऐसा करने की हिम्मत कहाँ से आती है ? उस नाकाबिल और जरपरस्त राजनीति से आती है जिसकी हैसियत 2014 में तब



नए नए चुने गए प्रधानमंत्री की पीठ पर हाथ रखकर मोटा भाई दुनिया भर को दिखा चुके हैं। जिन्हें अपने उत्पाद बेचने का मॉडल बनाकर विज्ञापनों में छपा चुके हैं। उस मीडिया से आती है जो इस बेहूदगी का लाइव प्रसारण करते और सेंट जी का महिमा गान करते हुए रीढ़विहीन होकर तलछट में रेंग रहा है और इसे राष्ट्रीय गौरव

बता रहा है। उस विचार समूह से आती है जिसकी मांद से निकले शाखा शृंगाल सेंट जी के इस शादी काण्ड में शामिल सारे अतिथियों के भारतीय (?) पोशाक पहनने को सनातन का दुनिया भर में प्रचार करने का कारनामा बताते हुए टि्वटर और इंस्टाग्राम पर कोहराम मचाये हुए हैं। यही है संघ जिन्हें अपना गुरु मानता है उन

गोलबलकर के आर्थिक सूत्र 'हाथी को मन भर चींटी को कण भर' के सूत्र को जनता के गले उतारने का जतन। सन्द रहे कि सेंट यह सारा तामझाम अपनी जेब से नहीं कर रहा है - उसने इसकी वसूली के लिए अपने जिओ के दाम झटका से बढ़ा दिए हैं। सेंट जी हमारी आपकी जेब से रोशनी चुराकर अपनी चमकार का मेला लगाए बैठे हैं।

अपराध

राजेंद्र बज

लेखक संभकार हैं।



समाचार पत्रों की सुखियों के बीच एक ऐसी खबर आई जिसे पढ़कर दिल दहल गया। मामला यह है कि चंदेरी में एक पिता ने अपने चार-पांच वर्षीय बच्चों को उल्टा लटका कर उनकी जमकर पिटाई की। कारण महज इतना था कि ऐसी पिटाई का बाकायदा वीडियो बनाकर मायके रह रही पत्नी को प्रताड़ित किया जा सके। हालांकि पत्नी की शिकायत पर दोषी के विरुद्ध कार्रवाई होगी, लेकिन यह घटना अपने आप में बहुत कुछ कहती है। मानव मन में स्वाभाविक रूप से रहने वाली संवेदनाओं और नैतिक मूल्यों के विलोपन की ओर इंगित करती यह घटना, काफी हद तक आदमी के वैचारिक दृष्टिकोण में आते जा रहे परिवर्तन को रेखांकित करती है। दरअसल वर्तमान आपाधापी के दौर में आदमी केवल और केवल अपने लिए ही सोचने लगा है। कल तक संयुक्त परिवार हुआ करते थे। उसमें दो से तीन पीढ़ी के परिजन भी साथ-साथ रहा करते थे। एक प्रकार से परिवार में बच्चों का नटखटपन, युवाओं का जोश और बुजुर्गों का अनुभव साथ-साथ चला करता था। लेकिन जब से विभिन्न परिस्थितियों के चलते एकल परिवारों का चलन बढ़ने लगा, वैसे-वैसे एकल परिवार में वैचारिक मतभेद के चलते तनाव की स्थितियाँ निर्मित होने लगीं। हालांकि पति-पत्नी या पिता-पुत्र के बीच की तकरार को संयुक्त परिवार के वरिष्ठजन थाम लिया करते थे। लेकिन एकल परिवार में जब दोनों ही पक्ष परस्पर टकराव की स्थिति में आ जाए, तो उन्हें कौन समझाए कि कौन सही और कौन गलत ? ऐसे में बच्चों का स्वाभाविक विकास अवरुद्ध होकर उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। इसकी परिणति यह होती है कि पति-पत्नी अलग रहने लगते हैं और बच्चे माता तथा पिता के संयुक्त साये से छिटककर रह जाते हैं। ऐसे में कभी बच्चों को मां का आंचल नहीं मिल पाता, तो कभी पिता रूपी कवच का साथ नहीं मिल पाता। यही नहीं अपितु बच्चों के बालमन में परिवार के प्रति किसी प्रकार की आसक्ति का भाव भी पनप नहीं पाता। नतीजा यह निकलता है कि एकल परिवार का हर सदस्य केवल और केवल अपने बारे में सोचने लगता है।

क्रूरता की पराकाष्ठा- कारणों पर भी विचार जरूरी



चंदेरी की घटना निश्चित रूप से ऐसी ही परिस्थितियों की उपज रही होगी। अन्यथा कोई कारण नहीं कि कोई पिता अपने बच्चों के प्रति इतना क्रूर हो जाए। उक्त घटना के बहाने ही सही, लेकिन आज के दौर में संयुक्त परिवारों के महत्व को समझने की नितांत आवश्यकता है। अन्यथा एकल परिवार में कब किसी का अहम उसके विवेक पर भारी पड़ जाए, इस बारे में पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। सहसा इस बात पर विश्वास नहीं होता कि कोई पति अपनी पत्नी को प्रताड़ित करने के निमित्त बच्चों को उल्टा लटका कर उनकी जमकर पिटाई करें। सचमुच यह घटना मात्र पारिवारिक अंतर्कलह की ही कहानी नहीं है, लेकिन इसानी फितरत में केवल और केवल अपने ही बारे में सोचने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। वास्तव में भीतिकता की चकाचौंध में आदमी इस कदर खोने लगा है कि अपनी जिंदगी को केवल अपनी ही जिंदगी के प्रति समर्पित रखने का बीड़ा उठाए हुए हैं। यह एक स्थापित तथ्य है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास में संयुक्त परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका रहा करती है। एकल परिवार होने की दशा में आमतौर पर अनुशासन, मर्यादा और नैतिकता को ताक पर रखे जाने का अंदेश हर समय बना रहता है। किसी भी प्रकार की उच्च-नीच हो जाने की स्थिति में भावावेश में आकर एकरतर्फा विचारों को मूर्त रूप दे दिया जाता है। चाहे वह विचार कितना ही अव्यावहारिक क्यों न हो ! जाहिर है कि इसका सीधा असर बच्चों पर हुआ करता है। आमतौर पर वे कुंठा से घिर जाया करते हैं। अब यह तो स्पष्ट है कि आज के बच्चे कल का समाज और आगे जाकर राष्ट्र का महत्वपूर्ण घटक बनेंगे। ऐसे में उनमें स्वाभाविक रूप से विकसित हो जाने वाले आत्मबल का क्या होगा ?

